सर्वहारा दृष्टिकोण

सोशलिस्ट यूनिटी सेन्टर ऑफ इण्डिया (कम्युनिस्ट) का मुखपत्र (पाक्षिक)

वर्ष-29 अंक-11 7 से 21 जून, 2014 मुख्य संपादक - कॉमरेड कृष्ण चक्रवर्ती मूल्य : 2 रुपये

16वें लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत पर एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) पोलिट ब्यूरो

सोशलिस्ट यूनिटी सेण्टर ऑफ इण्डिया (कम्युनिस्ट) के पोलिट ब्यूरो ने 21 व 22 मई 2014 को कोलकाता में हुई अपनी पिछली बैठक में हाल ही में हुए चुनावों के साथ-साथ चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद पैदा हुए सम्पूर्ण हालात का जायजा लिया।

संक्षेप में पोलिट ब्यूरो ने पाया कि पूँजीपति-परस्त और जनविरोधी नीतियों, भ्रष्टाचार में लिप्तता और कांग्रेस-नीत यूपीए सरकार के घोर कुशासन ने लोगों का जीवन दयनीय बना दिया था जिसके चलते कांग्रेस के खिलाफ लोगों में गहरा आक्रोश और यहाँ तक कि नफरत पैदा हो गई थी, इसके खिलाफ ताकतवर वाम जनवादी आन्दोलन के अभाव में वृद्धि और विकास के अपने अति कपटपूर्ण नारे के साथ तथा प्रत्यक्ष व परोक्ष साम्प्रदायिक प्रचार के जरिए बीजेपी परेशान जनता को काफी हद तक गुमराह करने में सफल रही।

दूसरी तरफ, अपनी मरणासन्न अवस्था में निरन्तर बढ़ते असमाधेय संकटों में डूबे विश्व पूँजीवाद का अभिन्न अंग होने के नाते भारतीय अर्थव्यवस्था भी गहरे संकट में है। विशेषकर 2008 की अभूतपूर्व मंदी के बाद जिसने पूँजीवाद की बुनियाद को ही हिला कर रख दिया था और जिससे उबरने की कोई संभावना नहीं है। इस स्थिति में शासक वर्ग भयाक्रांत होकर जन आन्दोलन के बढ़ते रुझान को उत्सुकता से देख रहा है। जनाक्रोश बहुत बार स्वत:स्फूर्त रूप में फूट पड़ता है। इस स्थिति से भयभीत जो कभी भी नियंत्रण से बाहर जा सकती है शासक बुर्जुआ वर्ग, विशेषकर अति शक्तिशाली कॉरपोरेट घराने अपनी पसंद की ही एक पार्टी और एक नेता की खोज में थे जो पूँजीवाद को इसके विनाश से बचाने वाली नीतियों को निरन्तरता और कभी-कभी प्रचण्डता के साथ लागू कर सके। अंतत:, बीजेपी के रूप में ऐसी एक पार्टी और नरेन्द्र मोदी के रूप में ऐसा एक नेता उन्हें मिल गया जिसने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर कॉरपोरेट घरानों को अति निष्ठावान सेवाएं प्रदान करके, खासतौर से उन्हें यह आश्वासन देकर कि उनकी सरकार मजदूर आन्दोलन बर्दाश्त नहीं करेगी, अपनी पात्रता पहले ही सिद्ध कर दी थी। स्वाभाविक रूप से, शासक पूँजीपति वर्ग, विशेषकर कॉरपोरेट घराने अब तक की अपनी सबसे भरोसेमंद पार्टी कांग्रेस को अपना समर्थन देना रोक दिया जो लोगों के गुस्से का निशाना बन चुकी थी और इसके अन्य विकल्प बीजेपी को और इसके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को सामने लाने में तमाम जरूरी मदद और सहायता प्रदान की।

इस स्थिति का फायदा उठा कर बीजेपी और विशेषकर मोदी ने लोगों, विशेषकर नौजवानों को गुमराह करने के लिए जोरशोर से वृद्धि और विकास का नारा उठाया जो पूँजीवाद की इस मरणासन्न अवस्था में न पूरा हो सकने वाला एक सपना है, जबकि बहुत ही शातिराना

(शेष पृष्ठ 2 पर)

बदायूँ सामूहिक दुष्कर्म काण्ड

राज्यव्यापी विरोध दिवस पर जगह-जगह रोष प्रदर्शन

मुख्यमंत्री, उ.प्र. सरकार को भेजे ज्ञापन

मुरादाबाद : उ.प्र. के बदायूँ सामूहिक दुष्कर्म काण्ड जिसमें दो नाबालिग चचेरी बहनों को बलात्कार के बाद पेड़ से लटका दिया गया, के विरोध में 2 जून को एआईडीवाईओ, एआईएमएसएस, एआईडीएसओ की ओर से जिलाधिकारी कार्यालय पर जोरदार रोष प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन का नेतृत्व एआईडीवाईओ के मुरादाबाद जिला अध्यक्ष विनोद विग, सचिव मौ. गौरी, एआईडीएसओ की जिला अध्यक्ष कॉ. ऋतु चौधरी, सचिव फैज खान, एआईएमएसएस की संयोजिका रामेश्वरी देवी तथा माया राजपूत ने किया।

कलैक्ट्रेट पर पहुँच कर प्रदर्शन विरोध सभा में तब्दील हो गया। सभा को मुरादाबाद के जाने-माने साहित्यकार माहेश्वर त्रिपाठी तथा जाने-माने चित्रकार डॉ. नरेन्द्र ने सम्बोधित करते हुए कहा कि आज उ.प्र. एक क्राईम प्रदेश बन गया है। यह रोष प्रदर्शन सिर्फ अपराधियों के ही खिलाफ नहीं बल्कि इस अपराध में पुलिस की संलिप्तता और अपराधियों को संरक्षण दे रही

(शेष पृष्ठ 2 पर)

बदायूं काण्ड की निन्दा

उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के कटरा गांव में दो नाबालिग लड़कियों से किये गये बलात्कार और हत्याकाण्ड पर ऑल इण्डिया महिला सांस्कृतिक संगठन (एआईएमएसएस) की अखिल भारतीय कमेटी ने 30 मई को जारी बयान के जरिये अपना गहरा शोक प्रकट किया। मीडिया में आई खबर के मुताबिक मां-बाप और ग्रामीणों की ओर से शिकायत किये जाने के बावजूद पुलिसवाले अपराधियों को पकड़ने के प्रति उदासीन थे। अभी तक तमाम अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। एआईएमएसएस ने उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की कि बाकी आरोपियों को भी तुरन्त गिरफ्तार किया जाये, पूरी घटना की निष्पक्ष जांच कराई जाये और दोषी पुलिसवालों सहित अपराधियों को कड़ी सजा दी जाये।

बदायूं काण्ड के विरोध में प्रदर्शन करते एआईडीवाईओ, एआईडीएसओ, एआईएमएसएस के कार्यकर्ता

बदायूँ सामूहिक दुष्कर्म काण्ड

(पृष्ठ 1 का शेष)

सरकार के भी खिलाफ है। उन्होंने कहा कि भारी जनदबाव में कानून तो बना था बलात्कारियों को फाँसी पर लटका देने के लिए लेकिन उ.प्र में उलटा हो रहा है। बलात्कारी मासूम बालिकाओं से बलात्कार कर उन्हें फाँसी पर लटका रहे हैं। जो सरकार 'पढ़े बेटियाँ, बढ़े बेटियाँ' का नारा देती है लेकिन वह बलात्कारियों के पक्ष में खुलेआम खड़ी है। प्रदेश में सत्ताधारी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव खुलेआम बलात्कारियों के पक्ष में बयान दे रहे हैं। इतना ही नहीं, बदायूँ की घटना में कई घण्टे लड़कियों की लाशें पेड़ पर लटकी रहीं लेकिन पुलिस नहीं आई।

बलात्कार तथा हत्याकाण्ड के दोषियों को फाँसी देने, महिलाओं तथा बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, टी.वी. तथा अन्य प्रचार माध्यमों द्वारा फैलाई जा रही अश्लीलता व अपसंस्कृति पर रोक लगाने व शराब तथा अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री व सेवन पर प्रतिबंध लगाने की मांग ज्ञापन में की गई।

सभा को कमलेश चहल, अंशु सक्सैना, भावना सिंह, सन्नोखान, कुलवंत सिंह, श्याम सुन्दर, राजबाला दीक्षित, भाषा तिवारी ने भी सम्बोधित किया।

अमरोहा (उ.प्र.): बदायूँ सामूहिक दुष्कर्म व हत्याकाण्ड के खिलाफ एआईडीवाईओ के प्रदेशव्यापी विरोध दिवस 2 जून को संगठन की जिला इकाई ने बदायूँ सामूहिक दुष्कर्म व हत्याकाण्ड पर रोष व्यक्त करते हुए कलैक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौपा।

प्रदर्शन का नेतृत्व संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष कॉ. राजेन्द्र सिंह ने किया। प्रदर्शनकारी जोरदार नारे लगा रहे थे–उ.प्र. सरकार होश में आओ, महिलाओं पर बढ़ते अपराध व बलात्कारों पर रोक लगाओ, प्रचार माध्यमों से अश्लीलता फैलाना बंद करो, शराब व नशाखोरी पर रोक लगाओ, बलात्कारियों व हत्या के दोषियों को फांसी दो।

इस प्रदर्शन को मुख्य वक्ता के रूप में सम्बोधित करते हुए संगठन के प्रदेश अध्यक्ष कॉ. हरकिशोर सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार व उसकी पुलिस खुलेआम अपराधियों व गुण्डों को संरक्षण दे रही है। सपा के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव द्वारा बलात्कारियों को बेचारे व उनकी करतूतों को गलती कहा गया जिससे उनके हौंसले बढ़े। पुलिस रक्षक नहीं भक्षक बनी हुई है।

इस अवसर पर नारंगपुर से ढक्का मोड़ तक सड़क की मरम्मत में धांधली, घटिया सामग्री व व्यापक भ्रष्टाचार के सम्बंध में जाँच करा दोषियों के खिलाफ कार्रवाई तथा गुणवत्तापूर्ण व मानकों के अनुसार सड़क मरम्मत की मांग को लेकर भी एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। प्रदर्शन को संगठन के जिला उपाध्यक्ष नासिर अली, सचिव नौबहार सिंह, गम्भीर सिंह, नरेन्द्र सिंह, सिद्धराज सिंह, जनम सिंह, वीरेन्द्र सिंह, धर्मपाल सिंह, कुशल कुमार, जोगेन्द्र सिंह ने भी सम्बोधित किया।

जौनपुर : बदायूँ व घोसी सहित उ.प्र. की अन्य जगहों पर लगातार बढ़ रहे सामूहिक दुष्कर्म काण्डों के विरोध में 2 जून को एआईडीवाईओ, एआईडीएसओ व एआईएमएसएस,की ओर से तिहसील मुख्यालय बदलापुर में रोष प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन का नेतृत्व एआईडीवाईओ के प्रदेश सचिव कॉ. रवि शंकर मौर्य ने किया। वहां हुई सभा की अध्यक्षता कॉ. दलीप कुमार ने की और संचालन कॉ विकास कुमार ने किया। मुख्यमंत्री के नाम 4 सूत्री मांग पत्र उपजिला अधिकारी बदलापुर को सौंपा।

बदायूं काण्ड के विरोधा में जौनपुर में प्रदर्शन करते एआईडीवाईओ, एआईडीएसओ व एआईएमएसएस के कार्यकर्ता

बदायूं काण्ड के विरोध में जेपीनगर में प्रदर्शन करते एआईडीवाईओ के कार्यकर्ता

16वें लोकसभा चुनाव...

(पृष्ठ 1 का शेष)

ढंग से उत्पीड़ित लोगों की विशाल संख्या को साम्प्रदायिक आवेग भड़का कर, हिन्दू राष्ट्रवाद को उकसाने के साथ-साथ अपना ठोस हिन्दू वोट बैंक तैयार करने के लिए हिन्दुओं के अन्दर तमाम जातियों का तुष्टिकरण करते हुए भ्रमित और गुमराह किया। इसके चलते धार्मिक आधार पर जनता का जबरदस्त ध्रुवीकरण हो गया। इस प्रकार पैदा किए गए घोर साम्प्रदायिक परिवेश ने पिछले तमाम रिकार्ड तोड़ दिए। फिर भी बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ अपनी जीत के लिए आश्वस्त नहीं थी इसे हासिल करने के लिए इसने तमाम कायदों और चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित आचार संहिता को धता बताते हुए तमाम तरह की धांधलियों को अपनाया। बहुमत सुनिश्चित करने के लिए, तमाम अन्य बुर्जुआ पार्टियों ने भी परोक्ष धमकियां और कहीं हिंसक तरीके अपनाते हुए बूथों पर कब्जे जैसे कदाचार को अपनाया जैसा कि विशेष तौर से पश्चिम बंगाल में हुआ। अत: चुनावों को किसी भी तरह से पूर्णत: स्वतन्त्र और निष्पक्ष नहीं कहा जा सकता है जैसा कि मीडिया दावा कर रहा है। जिसने अपने अभूतपूर्व प्रचार के जरिए बीजेपी की और मोदी की लहर पैदा करने का बेतहाशा मगर असफल प्रयास किया था। पोलिट-ब्यूरो ने यह पाया कि बीजेपी-मुखी तथाकथित लहर से अधिक जोरदार काग्रेस-विरोधी जन आवेग था जिसने केरल और कुछ हद तक कर्नाटक को छोड़कर सारे देश को अपने आगोश में ले लिया था। इसी से खुलासा होता है कि क्यों एआईडीएमके, तृणमूल, कांग्रेस, बीजेडी, टीडीपी और टीआरएस जैसी तमाम कांग्रेस-विरोधी ताकतें इस कांग्रेस-विरोधी परिवेश से लाभांवित हुई और बहुमत हासिल कर सकी जबकि बीजेपी इन राज्यों में बहुत कम प्रभाव पैदा कर सकी। लेकिन ये तमाम क्षेत्रीय बुर्जुआ पार्टियाँ भी पूरी तरह प्रतिक्रियावादी और जन-विरोधी हैं।

संक्षेप में, यह एक प्रतिक्रियावादी प्रवाह था जिसने वाम-जनवादी पार्टियों और ताकतों को लगभग हाशिए पर ला छोड़ा, इसका मूल कारण था स्वयंभू सीपीआई, सीपीएम और इसके सहयोगियों का घोर विश्वासघात, जनता के जनवादी आन्दोलन से पूरी तरह विमुख होना, उस समय भी जब चुनाव प्रचार के दौरान घोर साम्प्रदायिक वातावरण पैदा हो गया था। परिणाम विनाशकारी रहा। जनवादी तौर-तरीकों और दस्तूरों, विशेषकर धर्मनिरपेक्ष जनवादी मूल्यों पर आक्रमण तेज हो गए हैं। इसके चलते फासीवाद के तीव्र विकास के अति अनुकूल परिस्थिति तैयार हो गई है जिसे कांग्रेस द्वारा शुरू किया गया था।

इन हालात में, जब आम लोगों, विशेषकर मेहनतकश जनता का जीवन, आर्थिक-राजनीतिक, सांस्कृतिक क्षेत्र, संक्षेप में, जीवन के सभी क्षेत्र चौतरफा संकटों से घिरे हैं, विशेषकर नीति-नैतिकता के क्षेत्र में चौतरफा संकट व्याप्त है तब देशव्यापी संयुक्त सशक्त जनवादी जनआन्दोलनों में खुद को संगठित करने के सिवाय लोगों के पास कोई चारा नहीं है। उन्हें न केवल अपने जीवन के ज्वलंत मुद्दों के खिलाफ आन्दोलन संगठित करने होंगे बल्कि साथ ही साथ केन्द्र में साम्प्रदायिक बीजेपी और विभिन्न राज्यों में तमाम अन्य क्षेत्रीय बुर्जुआ प्रतिक्रियावादी पार्टियों के द्वारा सत्ता पर काबिज होने के बाद जो घोर साम्प्रदायिक और फासीवादी परिस्थिति तैयार हुई है उसके खिलाफ भी जनआन्दोलन संगठित करने होंगे। क्योंकि जनवादी परिस्थितियों के तहत ही जनआन्दोलन मुक्त रूप से उभर सकते हैं। इसलिए लोगों को धर्मनिरपेक्ष तौर-तरीकों और मूल्यों की बहाली और विस्तार के लिए संघर्ष की खातिर उठ खड़े होना होगा और इस प्रकार ही पूँजीपति वर्ग के आदेश पर फासीवाद के बढ़ते मौजूदा रुझान के खिलाफ प्रभावकारी ढंग से संघर्ष संचालित किया जा सकता है।

इसीलिए निहायत ही जरूरी है कि बीजेपी के तहत पूँजीपतियों के शासन के भयंकर आक्रमण का प्रतिरोध करने के लिए संघर्ष के नए रास्ते का निर्धारण किया जाए। तमाम फासीवाद-विरोधी जनवादपसंद ताकतों को संघर्ष के एक वृहद प्लेटफार्म पर एकजुट किया जाए और जीवन की ज्वलन्त समस्याओं पर एक देशव्यापी संयुक्त संगठित सशक्त आन्दोलन छेड़ा जाए जो आसन्न महाविपत्ति को रोकने में एक प्रभावकारी अवरोधक का काम करेगा। इस संघर्ष के सांस्कृतिक और भावगत परिवेश में निहित अनुकूल वातावरण ही शासक वर्ग द्वारा प्रायोजित प्रतिक्रियावादी ताकतों के खिलाफ एक जोरदार सैद्धान्तिक-सांस्कृतिक संघर्ष छेड़ा जाना सुनिश्चित करेगा। ●●●

साम्राज्यवाद और आतंकवाद

उत्पीड़ित जनता की आजादी के लिए जिन समझौताहीन योद्धाओं ने संघर्ष किया था उन्हें आतंकवादी कहकर बदनाम करना साम्राज्यवादी शोषकों का बहुत पुराना हथकण्डा रहा है। उनके गुलाम देश भी उनका यही काम करते रहे हैं। ब्रिटिश शासकों के खिलाफ आजादी आन्दोलन के समय भारत की जनता को इसका कटु अनुभव है। हमारे आजादी आन्दोलन की क्रान्तिकारी धारा के योद्धाओं पर आतंकवादी का ठप्पा लगाकर उन्हें फांसी के फंदे पर लटका दिया जाता था और समझौतावादी नेतृत्व की खातिरदारी की जाती थी, यहाँ तक कि उन्हें साम्राज्यवादी बढ़ा चढ़ा कर पेश करते थे। अन्यान्य देशों में भी इसी तरह की घटनाएं घटती थी। अंतर्राष्ट्रीय स्वाधीनता के प्रतीक नेल्सन मण्डेला को 27 साल तक जेल में बंदी बना कर रखा गया था। अमेरिका की 'टैररिस्ट वाच लिस्ट' में कुछ दिनों पहले तक उनका नाम था। केनया के जोमो केनियाट्टा, साइप्रस के आर्चबिशप मेकिराउस, जिम्बाब्वे के राबर्ट मूगाम्बे जैसे साहसी योद्धा, जो देश की स्वाधीनता के लिए लड़े थे उनको भी आतंकवादी का तमगा दिया गया था। जब भी जहाँ कहीं भी शासक-शोषकों के खिलाफ जिन्होंने हथियार उठाए हैं उन्हें आतंकवादी रूप में प्रताड़ित किया गया है। हालांकि साम्राज्यवादी जब बेबस नागरिकों पर घातक बमों की वर्षा करते हैं तब वे मुक्ति योद्धा के रूप में अभिनन्दित होते हैं। शीत युद्ध के दौरान साम्राज्यवादियों का एक प्रचार चालू था–अंतर्राष्ट्रीय 'आतंकवाद' के लिए सोवियत रूस की सीक्रेट सर्विस के क्रियाकलाप जिम्मेदार हैं। लेकिन अब तो सोवियत यूनियन टुकड़े-टुकड़े हो खण्डित हो गया है। प्रतिक्रान्ति ने समाजवाद को पराजित कर दिया है। लेकिन फिर भी दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जब लगभग आये दिन हिंसा की घटनाएं बदस्तूर घट रही हैं और वे बढ़ रही हैं तब यह प्रचार कितना झूठ था यह समझा जा सकता है। हमें समझना होगा कि लक्ष्य हासिल करने के लिए शान्तिपूर्ण जनवादी हर रास्ता जब अकार्यकारी हो जाता है केवल तभी आम आदमी अत्याचारियों के खिलाफ अन्तिम उपाय के रूप में हथियार उठाता है। मण्डेला ने अपनी आत्मकथा में लिखा है–''असल में सच्चाई यह है कि 50 वर्षों की अहिंसा नीति ने हमारे जनसाधारण को बहुत अधिक दमनात्मक कानून उपहार में दिए हैं,बदले में अधिकार बहुत ही कम दिए हैं।''

इतिहास गवाह है कि जब असहाय जनता पर अन्याय-अत्याचार ढाहा जाता है, उनके अधिकार छीन लिए जाते हैं, जब रोजी-रोटी से उन्हें वंचित कर दिया जाता है, जब वे देखते हैं कि जो लोग सत्तासीन हुए हैं वे उनकी न्यायसंगत मांगों को अनसुना कर रहे हैं तब उनकी असफलता, हताशा-निराशा हिंसात्मक क्रियाकलापों के जरिये प्रकट होती है। धन के बंटवारे में गैरबराबरी, राजसत्ता के खुल्लमखुल्ला संरक्षण में पूँजीपति वर्ग द्वारा सर्वहारा का शोषण, पिछड़े देशों का साम्राज्यवादियों द्वारा शोषण, पूँजीवादी देशों में अल्पसंख्यक समुदाय और अल्पसंख्यक उपराष्ट्रीयताओं पर दमन-उत्पीड़न सब कुछ इस आतंक की आग में घी का काम करते हैं। निहित स्वार्थी तत्व जनता की हताशा-निराशा, आक्रोश-क्षोभ से अपनी खुद की मांगों के प्रति समर्थन हासिल कर लेते हैं। किसी भी व्यक्ति विशेष के हिंसात्मक क्रियाकलापों के पीछे क्या उद्देश्य है यह लेकर हम यहाँ चर्चा नहीं कर रहे हैं। चर्चा इसको लेकर कर रहे हैं कि इसका मूल कारण किस आर्थिक-सामाजिक परिस्थिति पर निर्भर करता है। जनता हाथ में हथियार उठा लेती है क्योंकि सिर्फ इतना ही नहीं कि अत्याचारी शासकगण हथियारों से लैस हैं बल्कि जनता के न्यायसंगत आन्दोलनों को कुचलने के लिए भी वे बेरहमी से इन हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। इतिहास गवाह है कि जहाँ कहीं भी जनता का मुक्ति संग्राम विजयी हुआ है वहाँ यह विजय सशस्त्र संग्राम के माध्यम से प्राप्त हुई है। मैं यहाँ इस विषय पर जोर देना चाहता हूँ। आर्थिक एवं सामाजिक-राजनैतिक परिवर्तन का सुस्पष्ट लक्ष्य लेकर एक दृढ़ आदर्श के आधार पर जनता के संगठित सशस्त्र संग्राम के साथ इस कुण्ठित अवरुद्ध हताशा से हथियार उठा लेने की घटना का घोलमठ्ठा नहीं करना चाहिए।

(विगत 12-22 अप्रैल को टर्की के इस्ताम्बुल में पीपुल्स फ्रण्ट द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में आमंत्रित होकर एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) के पोलिट ब्यूरो सदस्य कॉमरेड माणिक मुखर्जी ने अपना वक्तव्य रखा। मूल अंग्रेजी वक्तव्य का हिन्दी अनुवाद दिया जा रहा है।)

मध्य-पूर्व के हालात इसका एक उज्जवल उदाहरण है। फिलस्तीनी जनता को उनके जन्मस्थान से बेदखल करके सत्तर वर्ष पहले जिस समय साम्राज्यवादियों ने षड्यन्त्र करके इस्राइल राष्ट्र की स्थापना की थी तब से ही संघर्ष की परिस्थिति और हिंसा के परिवेश की शुरूआत हुई थी। अपने जन्मकाल से ही इस्राइल देश ने लाखों-लाख अरब जनता के खिलाफ हिंसा और आतंक का सहारा लिया है और अत्यन्त आक्रामक रूप से साथ लगती जमीन और विभिन्न क्षेत्रों को दखल करता रहा है। इस इलाके के तमाम मूल निवासियों को शरणार्थी बना कर कैम्पों में धकेल दिया गया है। घोर गरीबी के बीच साल-दर-साल उन्हें रहने के लिए मजबूर किया गया है। एक पूरी पीढ़ी शिक्षा, स्वास्थ्य, मानवीय मर्यादा जैसी न्यूनतम परिसेवा के अभाव में बड़ी हुई है। फिलस्तीनी जनता के इस असहनीय कष्ट के प्रति इस्राइल और साम्राज्यवादी शक्तियाँ आंख मूंदे हुए हैं। इसके विपरीत साम्राज्यवादी ताकतें खासकर अमेरिका की प्रत्यक्ष मदद से इस समस्या के एक सम्मानजनक समाधान का रास्ता निकालने के प्रस्ताव की इस्राइल ने बार-बार अवहेलना की है। लाखों-लाख फिलस्तीनियों को सिर्फ उनके निवासस्थान से उजाड़ा ही नहीं गया है बल्कि इस्राइल ने नारी-शिशु-वृद्ध का खयाल किए बिना आम नागरिकों पर बम बरसाये हैं, हत्याएं की हैं, बुलडोजरों से उनके घरों को तहस-नहस करके लोगों को बेघर कर दिया है। ठीक इसी वजह से लोग गुस्से और क्षोभ के चलते अक्सर हिंसा का सहारा ले रहे हैं।

फिलस्तीनियों का प्रचण्ड क्रोध और साहस कैसा है यह बात सहज ही समझी जा सकती है। जब देखते हैं कि इस्राइल के टैंक आगे बढ़ रहे हैं और फिलस्तीन के बच्चे-किशोर तक सिर्फ हाथ में पत्थर लेकर उनका मुकाबला कर रहे हैं। हमलावरों के खिलाफ जिस किसी भी तरह की सशस्त्र जंगी लड़ाई को इस्राइल और उसके साम्राज्यवादी जिगरी दोस्त आतंकवाद की संज्ञा देते हैं। फिलस्तीनी चुनावों में जब हमास को भारी बहुमत से जीत हासिल हुई तब साम्राज्यवादियों ने अपने आतंक को छिपा कर नहीं रखा। इस जीत को मान लेने से उन्होंने मना कर दिया। हमास और फिलस्तीनी योद्धाओं के खिलाफ इस्राइल ने हमला शुरू कर दिया।

लैटिन अमेरिका, अफ्रीका सहित जहाँ जहाँ भी हिंसात्मक कार्रवाइयां हो रही हैं इसी तरह की चीजें देखी जा रही हैं। लैटिन अमेरिका के बहुत से देशों में भ्रष्टाचारी, स्वेच्छाचारी शासकगण अमेरिकी साम्राज्यवाद के साथ सांठगांठ रखते हुए उसकी मदद से चल रहे हैं। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने इन देशों को लूट कर आम जनता को घोर गरीबी में धकेल दिया है। जब भी इनके खिलाफ कोई जुझारू असरदार शक्तिशाली विरोधी संगठन समाजवादी पुनर्गठन का लक्ष्य लेकर निर्मित हुआ, विदेशी व्यापारिक संस्थाओं को उखाड़ फेंकना चाहा तभी उन पर आतंकवादी का लेबल चिपका दिया गया और उनका दमन करने के लिए साम्राज्यवादियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। कोई देश यदि अमेरिकी साम्राज्यवाद का सरासर विरोध करने का साहस दिखाता है तो उसे आर्थिक प्रतिबन्ध, सशस्त्र आक्रमण, नग्न आक्रामकता का सामना करना पड़ता है। क्यूबा और वेनेजुएला में इस समय ठीक यही हो रहा है।

अफ्रीका में सूडान अपनी आर्थिक सम्पदा को काम में लगा कर साम्राज्यवादियों के निर्देश को अस्वीकार करते हुए विकास की एक स्वतन्त्र नीति लेकर चलना चाहता था। अपने खुद के तेल भण्डार में अमेरिकी साम्राज्यवादियों को वह घुसने देना नहीं चाहता था। अमेरिकी साम्राज्यवाद के नेतृत्व में इराक युद्ध और कब्जे का उसने समर्थन नहीं किया था। इस घटना से अमेरिकी साम्राज्यवाद खफा हो गया। इसीलिए उसने अपने साम्राज्यवादी जिगरी दोस्तों के साथ मिल कर सूडान के राष्ट्रपति उमर हसन अल बसर को युद्ध-विरोधी एवं मानवता का शत्रु करार देकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट में घसीटने का षड्यन्त्र रचा। सिर्फ इतना ही नहीं, सूडानी जनता के बीच उपराष्ट्रीय जातीय दंगे को भड़का कर दक्षिणी सूडान को छिन्न-भिन्न कर दिया। युगोस्लाविया में स्लोवोदान मिलोशोविच साम्राज्यवादी चतुराई और देश के अन्दर अस्थिरता पैदा करके देश को टुकड़े-टुकड़े कर देने के खिलाफ डटकर खड़े हो गए थे। भयंकर घातक के रूप में साम्राज्यवादियों ने उनके खिलाफ प्रचार चलाया और मानवता के शत्रु के रूप में अपराधी सिद्ध करके पूर्ववर्ती युगोस्लाविया के लिए गठित किए गए राष्ट्र संघ के अंतर्राष्ट्रीय अपराध ट्रिब्यूनल में उनको घसीट लाए।

तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने आतंकवाद के खिलाफ विराट उच्च नैतिक स्टैण्ड की घोषणा की और 'आतंकवाद के खिलाफ विश्वव्यापी युद्ध' शुरू करके इराक और अफगानिस्तान को ध्वस्त कर दिया था। सीरिया और ईरान सरकार के खिलाफ आतंकवादी का ठप्पा लगा कर प्रचार चलाते हुए राष्ट्रपति बराक ओबामा इसी तरह की नीति का अनुसरण कर रहे हैं एवं उसे और भी विस्तृत कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका का लम्बा इतिहास है कि अपने खुद के प्रभाव को बढ़ाने के लिए उसने अन्यान्य विभिन्न देशों में आतंकवादी संगठनों का समर्थन किया है। उनको मदद पहुँचाई है। युगोस्लाविया की कसोवा लिबरल आर्मी, जूनदल्लाह या ईरानियन पीपल्स रेजिस्टेन्स मूवमेण्ट और ईरान के मुजाहिदीन-ए-खालेक या एमईके, अफगानिस्तान के मुजाहिदी, अर्मेनिया के तालाक के प्रति अमेरिका का समर्थन सर्वविदित है। इनमें से बहुतों ने अमेरिका में प्रशिक्षण लिया है। जिन्होंने अमेरिका का विरोध किया था वहाँ आतंकवादी हमला करने के लिए अमेरिका ने धन और समर्थन मुहैया कराया था। अफगानिस्तान में हजारों-हजार आतंकवादियों को भीतरघात करने, बम बनाने और शहरों में गोरिल्ला युद्ध कौशल का प्रशिक्षण अमेरिका ने दिया था। यहाँ तक कि ओसामा बिन लादेन को उसके अफगान 'जेहाद' के समय अमेरिकी सरकार ने भारी मात्रा में धन दिया था ऐसी खबरें प्रकाशित हुई थीं। जनतंत्र को समर्थन के नाम पर वे सीरिया के विद्रोहियों को हथियार मुहैया करा रहे हैं। इस देश के स्थायित्व को खत्म कर देने के लिए गृहयुद्ध छेड़ने की खातिर सक्रिय मदद दे रहे हैं।

अमेरिका के जार्जिया प्रदेश में एक आतंकवादी प्रशिक्षण केन्द्र 50 वर्षों से भी अधिक समय से धन मुहैया करा कर अमेरिकी सरकार चला रही है। केन्द्र का नाम 'वेस्टर्न हेमिस्फीयर इन्स्टीच्यूट फॉर सिक्योरिटी कॉरपोरेशन' (पहले जिसका नाम स्कूल ऑफ अमेरिका था) लैटिन अमेरिका के सबसे अत्याचारी शासकगण नरसंहारक, स्वेच्छाचारी एवं राष्ट्रीय आतंकवादी सब इसी प्रशिक्षण केन्द्र से प्रशिक्षित हैं। गुयटामाला, अल सलवाडोर, पनामा, चिली, कोलम्बिया सहित अन्याय देशों में नृशंस अत्याचारों के लिए यही जिम्मेदार हैं।

किसी भी शासन या देश को शत्रु मान कर उस देश को नेस्तनाबूद कर देने के लिए हर तरह के आतंकवादी क्रियाकलापों में मदद देने की जो अमेरिकी नीति है–उसी नीति के फलस्वरूप भस्मासुर तैयार हुए हैं। इन्होंने अंततः अमेरिका के खिलाफ ही अपनी बंदूकों का रुख मोड़ दिया है। यही थी ओसामा बिन लादेन की कहानी।

सर्वविदित है कि इस तरह बहुत उदाहरण है जहाँ अमेरिका ने समर्थन देकर, धन देकर, युद्ध के साजो सामान देकर किस प्रकार अत्याचारी, स्वेच्छाचारी सरकारों की सहायता की है एवं चुनावों के जरिए सरकार पलटने में हर तरह की बाधाएं खड़ी की हैं। बहुत वर्षों से उन्होंने पनामा के नरियेगा एवं चिली के पिनोचेट जैसे भयंकर

(शेष पृष्ठ 4 पर)

साम्राज्यवाद और आतंकवाद

(पृष्ठ 3 का शेष)

अपराधी तानाशहों की सहायता की है। गुवाटामाला, अल-सलवाडोर, चिली, अर्जेण्टिना कोलम्बिया की अमेरिकी मदद प्राप्त सरकारों ने अकथनीय अकल्पनीय नृशंस करतूतें की हैं, हत्याएं की हैं, उपराष्ट्रीय दंगा भड़काया है। उन्होंने मजदूरों, किसानों, छात्रों, युवाओं और युवतियों को कुत्तों की तरह दुत्कार कर भगाया, अत्याचार किया, आतंक बरपाया और हत्याएं की हैं। ये अमेरिका की मदद से ही चले हैं और अमेरिका ने उनका खजाना भरा है, मिलिट्री सहायता सहित सब तरह की सहायता दी है, आतंकवादी क्रियाकलापों की रणकौशल बना कर दी है और कूटनीतिक रूप में भी सहायता की है।

इस्राइल ने अरब क्षेत्र की जो जमीन हथियारों के बल पर कब्जा ली है और फिलस्तीनी जनता के खिलाफ अस्त्र-शस्त्र, युद्धक विमान, टैंक लेकर जो युद्ध चलाता जा रहा है वह शस्त्रों सहित तमाम तरह की सहायता अमेरिका उसको मुहैया करा रहा है। इस्राइल के पास परमाणु हथियार होने को लेकर अमेरिकी शासक मौन हैं। लेकिन ईरान के खिलाफ परमाणु हथियार तैयार करने का झूठा आरोप लगाकर हमला करने के लिए वे तत्पर हैं। अब वे ईरान को धमकी दे रहे हैं। हालांकि इरान ने सुस्पष्ट रूप से बता दिया है कि उनके परमाणविक क्रिया कलाप पूरी तरह से शान्तिपूर्ण उद्देश्य के लिए हैं।

हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में अमेरिकी सरकार ने फौजी तानाशाह मुशर्रफ के साथ हाथ मिलाया था। इसी मुशर्रफ ने व्यक्ति अधिकार और स्वाधीनता का गला घोंट दिया था। समाज की घोर कट्टरपंथी ताकतों को मदद दी थी। दुनियाभर में अत्याचारी और हत्यारों के पक्ष में अमेरिकी सरकार खड़ी है इसके फलस्वरूप अमेरिका के खिलाफ आक्रोश, क्षोभ, घृणा व्याप्त है। इसीलिए अमेरिका के खिलाफ आक्रमण को इन तमाम देशों की जनता का परोक्ष समर्थन प्राप्त हो रहा है। लेकिन इससे अमेरिकी शासक समाप्त नहीं हो रहे हैं। क्यों विभिन्न देशों में जनता अमेरिकी नीति से घृणा करती है–इस बारे में जिस किसी भी तरह की तर्कपूर्ण चर्चा-बहस को अमेरिकी शासक 'आतंकवाद की हिमायत करने' का बावेला मचा कर दबा देते हैं। अमेरिका इस बात को समझ नहीं पा रहा है कि हिंसा हमेशा हिंसा को जन्म देती है।

वियतनाम में अमेरिकी वीभत्सता की कहानी हम सभी जानते हैं। जापान जब लगभग आत्मसमर्पण करने जा रहा था तब हिरोशिमा-नागासाकी पर परमाणु बम गिराने की बात भी किसी से अज्ञात नहीं है। आतंकवादी हिंसा से ये सब क्या किसी भी तरह से अलग हैं? 1959 से यही सीआईए और पेण्टागन क्यूबा के खिलाफ अनेक तरह के आतंकवादी क्रियाकलाप चलाते जा रहे हैं। फिदेल कास्त्रो की हत्या का प्रयास किया है जो प्रयास अभी भी जारी है, खास कर समाजवादी खेमा ध्वस्त हो जाने के बाद अमेरिका एवं मध्य अमेरिका आधारित आतंकवादी संगठनों के क्रियाकलापों में बढ़ोतरी हुई है। क्यूबा वेनेजुएला में जो सब अपराधी आतंकवादी कामों के लिए दोषी पाए गए उन्होंने अमेरिका में राजनैतिक शरण लेनी चाही और उन्हें मिल भी गई। दूसरी तरफ क्यूबा के बहुत से नागरिकों को अमेरिकी जेलों में झूठे आरोप लगा कर कैद में डाल रखा है।

सन 1990 के दशक में निकारागुआ सीआईए की मदद प्राप्त दक्षिणपंथी आतंकवादी गुट कोण्ट्रा और अमेरिका के भयावह आक्रमण का शिकार हुआ था। हजारों हजार लोग मारे गए। देश खण्डहर में परिणत हो गया। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने अमेरिका को 'गैर कानूनी बल प्रयोग' के अभियोग का अभियुक्त बनाया और उपयुक्त हरजाना देने का निर्देश दिया। सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र की जनरल काऊन्सिल ने इस क्रिया कलाप की निन्दा की थी लेकिन अमेरिका ने किसी पर भी अमल न करके सिरे से खारिज कर दिया। 1985 में बेरूत के एक मुस्लिम मौलवी की हत्या करने के लिए रेगन प्रशासन ने एक आतंकवादली बम हमले का षड्यन्त्र रचा। लेकिन इस हमले में कम से कम सैकड़ों आम लोग घायल हुए और मारे गए। रासायनिक हथियार तैयार करने का आरोप लगा कर 1998 में सूडान के एक दवाई बनाने के कारखाने पर उन्होंने मिसाइल से हमला किया था। लेकिन बाद में यह आरोप झूठा साबित हुआ। सूडान में बनने वाली 60% दवाइयां इसी कारखाने में तैयार होती थी। कारखाना ध्वस्त हो जाने की वजह से यह उत्पादन बन्द हो गया। इराक के खिलाफ पहले हमले के बाद अमेरिका ने जो आर्थिक प्रतिबंध लगाया था इसके चलते बच्चों सहित लाखों-लाख आम नागरिकों की मौत हो गई। दूसरी बार हमले और देश पर कब्जे के परिणामस्वरूप उस देश का सब कुछ ध्वस्त हो गया उसका सामाजिक-राजनैतिक बुनियादी ढांचा विलुप्त हो गया। उस देश को भ्रातृघाती दंगों में धकेल दिया गया। बाहर से देखने पर लगेगा कि मानो ये बेकाबू हो गये हैं। लगभग हर रोज या तो इस गुट नहीं तो दूसरे गुट की हिंसा में मासूम नागरिकों की जान जा रही है। सिर्फ बम बरसा कर और मिलिट्री उतार कर साम्राज्यवादियों ने अफगानिस्तान को ध्वस्त किया है, यही अमेरिका मांग कर रहा है कि पाकिस्तान जो अफगानिस्तान को खाद्य सहायता कर रहा है उसे बन्द करना होगा ताकि अफगानिस्तान के असैनिक लोग भूख से मर जाएं।

देश देश में प्रकट और गुप्त सशस्त्र हमला और हस्तक्षेप के लम्बे इतिहास को बयान करते हुए नाओम चामस्की ने अमेरिका को 'अग्रणी आतंकवादी राष्ट्र' कहकर निन्दा की है। प्रिंस्टन यूनिवर्सिटी के इतिहास के अमेरिटस अध्यापक अर्नो मायेर कहते हैं कि 1947 से शुरू कर उसके बाद के समय में एकतरफा राष्ट्रीय हमला या आतंक चलाने के सवाल पर अमेरिका ही मुख्य रूप से जिम्मेदार है इतना ही नहीं बल्कि इस चीज को शुरू भी उन्होंने ही किया था।

सीरिया के सशस्त्र संघर्ष में साम्राज्यवादी ताकतें प्रकट रूप से उन विद्रोही गुटों को समर्थन दे रही हैं जो सरकार के खिलाफ सामरिक अभियान में उतरे हैं और निर्लज्ज होकर सीरिया के राष्ट्रपति बशर-अल-असद के पदत्याग की मांग कर रहे हैं। इनके क्रियाकलाप ही सीरिया में गृहयुद्ध की परिस्थिति को और भी भयानक बना रहे हैं जिसके चलते साधारण लोग मृत्यु और विध्वंस का शिकार बन रहे हैं। साम्राज्यवादियों का अंततः षडयन्त्र प्रकट हो रहा है यूक्रेन के नकारात्मक घटना प्रवाह में। वहाँ वे विभिन्न विक्षुब्ध गुटों को मदद देकर सरकार-विरोधी विक्षोभ पैदा कर रहे हैं ताकि निर्वाचित राष्ट्रपति इयानुकोविच को हटा कर एक कटपुतली सरकार बैठा दी जाए।

इराक की अबूगरेब जेल के कैदियों पर अत्याचार और क्यूबा उपसागर में स्थित गुयंतानामो जेल के कैदियों पर नृशंसता की कहानी अमेरिका के फासीवादी चरित्र को उजागर करती है। लीबिया, सीरिया, सूडान, अफगानिस्तान, इराक, मध्य अमेरिका में साल दर साल मासूम लोगों पर बम बरसा रहा है अमेरिका। यह सूची और भी लम्बी हो रही है। सैकड़ों हजार मासूम लोगों की जब जी चाहे हत्या करना यदि आतंकवाद नहीं है तो आतंकवाद किसे कहा जाएगा?

आज भूमण्डलीकरण के नाम पर साम्राज्यवादी ताकतें और उनके ताबेदार देश-देश में आम लोगों को भयंकर शोषण का शिकार बना रहे हैं जीविका हरण, बेरोजगारी, बेदखली इत्यादि लगातार बढ़ रही है। शोषित-पीड़ित जनता चूँकि शोषणमूलक व्यवस्था के खिलाफ प्रतिवाद में संगठित हो रही है, इसीलिए पूँजीवादी शासक उनके न्यायसंगत आन्दोलन को दबाने के लिए राजसत्ता का इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी-कभी सरकार अपने देश की जनता का गला घोंटने के लिए उनको आर्तकित कर रही है। विरोधियों के लिए दिखावटी न्याय विचार, राजसत्ता जिन्हें शासन व्यवस्था का शत्रु मानती है, उनके नजदीकी रिश्तेदारी और दोस्तों को भी सजा देना, पुलिस और सेना वाहिनी का इस्तेमाल पूँजीवादी देशों में भयावह रूप से बढ़ रहा है। बीच-बीच में राजसत्ता के लिए विपत्तिजनक लगने वाले ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सरकारी अधिकारी या 'घातक वाहिनी' आतंकी रणकौशल से आपरेशन चलाती है। गैर-सरकारी किसी भी आतंकवादी संगठन को सरकार जब रुपया-पैसा, शस्त्र-प्रशिक्षण सहित विभिन्न तरह की सहायता देती है तब यह भी राजसत्ता के आतंकवाद का ही एक रूप है। अमेरिका को इस तरह के क्रियाकलापों का चैम्पियन कहा जा सकता है।

आतंकवाद को रोकने के नाम पर नागरिक अधिकारों का हनन करना भी साम्राज्यवादी ताकतों की एक रणनीति है। राष्ट्रपति बुश ने घोषणा की थी कि 'स्वाधीनता आक्रांत है, लेकिन स्वाधीनता पराजित नहीं होगी।' लेकिन गुप्त रूप से समन पकड़ा देना, गिरफ्तार करना, कैद में रखना, गुप्त रूप से मुकदमा चलाना इन सब के माध्यम से लोगों की स्वाधीनता सबसे ज्यादा खतरे में पड़ी है अमेरिका में 9/11 के बाद से ही। अमेरिका में 9/11 के बाद विभिन्न तरह की नीतियाँ अपनाई गई हैं जैसे कि फौजी अदालत में मुकदमा चलाना, गुप्त रूप से कैदी बना कर रखना, उनसे जिरह करने के नाम पर दूसरे देश के गुप्त ठिकाने पर चालान कर देना, वहाँ पर हत्या करके शव को गायब कर देना ये सब अमेरिकी प्रशासन के फासिस्ट चरित्र को उजागर करता है। हमें समझने की जरूरत है कि एकाधिकारी पूँजी और साम्राज्यवाद के इस युग में तमाम पूँजीवादी देश अपनी केन्द्रीकृत अर्थव्यवस्था, केन्द्रीकृत प्रशासन और सैनिक-औद्योगिक गुट की शक्ति लेकर कमोबेश फासिस्ट चरित्र अर्जित कर रहे हैं। आधुनिक फासीवाद हर समय सर्वशक्तिमान तानाशाह का रूप लेकर नहीं आता है। संसदीय जनतंत्र के मुखौटे की आड़ में ही फासीवाद आता है। फासीवाद के लक्षण हैं राजसत्ता के हाथ में क्षमता का केन्द्रीकरण, अर्थव्यवस्था का सम्पूर्ण केन्द्रीकरण और अन्धता-उन्माद-उग्र राष्ट्रवादी मानसिकता को जन्म देकर पैदा किया गया ऐसा सांस्कृतिक परिवेश।

हमारा देश भारत भी इसका अपवाद नहीं है। भारत सिर्फ एक पूँजीवादी देश ही नहीं है बल्कि इसने साम्राज्यवादी चरित्र अख्तियार कर लिया है और राजसत्ता के फासीवादी लक्षण लगातार उभर कर सामने आ रहे हैं। शासक वर्ग नागरिक अधिकारों का हनन कर रहा है। जनवादी आन्दोलनों का दमन कर रहा है, राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय कॉरपोरेट कम्पनियों के हितरक्षा नग्न रूप से कर रहा है और जात-पात, साम्प्रदायिकता व उग्र राष्ट्रवाद की आग को भड़का रहा है। जिस किसी भी तरह की विरोधिता का कठोरता से दमन किया जा रहा है। पुलिसी हत्या, सुरक्षा बलों के द्वारा हत्या, दमन उत्पीड़न, राजनैतिक कार्यकर्ताओं को गैर कानूनी ढंग से कैद में डाल देना, बिना मुकदमे जेल-हवालात-आज हर रोज की स्वाभाविक घटना हो गई है।

साम्राज्यवाद ही आतंकवादी क्रियाकलापों का सरगना है। आतंकवाद है साम्राज्यवाद द्वारा उगाई गई फसल। प्रत्येक शान्तिकामी आदमी जो आतंकवाद मुक्त एक धरती चाहते हैं। उन्हें साम्राज्यवाद और पूरी दुनिया को अपने चंगुल में लाने की इसकी भयावह साजिश के पंजे से धरती को मुक्त करना होगा। भूमण्डलीकरण के नाम पर अमेरिकी साम्राज्यवाद के नेतृत्व में साम्राज्यवादी शक्तियाँ पूरी दुनिया को लूट कर अपनी खुद की जेबें भर रही हैं। ये प्रत्येक देश की आर्थिक नीति निर्धारित करने में हस्तक्षेप कर रही हैं और उन देशों की राजनीति को भी नियंत्रित करना चाहती हैं।

वेनेजुएला, उत्तर कोरिया या ईरान–वहीं पर प्रतिरोध का केन्द्र बन गया है, वहीं पर आर्थिक पाबंदी, अवरोध, सैनिक हस्तक्षेप यहाँ तक कि सरासर हमले और कब्जा कर लेने का भय दिखाया जा रहा है। साम्राज्यवाद के जघन्य षड्यन्त्रों के शिकार इन देशों की सहायता के लिए दुनिया के प्रत्येक जनवादपसंद आदमी को आगे आकर इनके समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय जनमत को संगठित करने का आह्वान करता हूँ। देश-देश में साम्राज्यवाद-विरोधी संघर्ष संगठित करने के जरिए ही केवल साम्राज्यवाद-विरोधी संघर्ष संगठित करने के जरिए ही केवल साम्राज्यवाद को पराजित करना संभव है और मानव द्वारा मानव के शोषण के खिलाफ जो मुक्ति संघर्ष है उसके ही परिपूरक के रूप में इसे संगठित करना होगा। यह यदि हम संगठित कर सके और दुनिया भर में यदि एक सुसंगठित रूप दे सके तो हम साम्राज्यवाद को परास्त कर सकेंगे। केवल इसी तरह से आतंकवाद का खात्मा होगा। यही लक्ष्य लेकर एआईसीसी गठित हुई है। साम्राज्यवादी आक्रमण के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई करते हुए दुनिया को इन नर-संहारकों के हाथ से मुक्त कराने के लिए हम सभी का आह्वान करते हैं। केवल इसी तरह से हम आतंकवाद-मुक्त धरती की कल्पना कर सकते हैं। जहाँ प्रत्येक मनुष्य शान्ति और मर्यादा के साथ रह सकता है। ★★★

कक्षा 9वीं के खराब परीक्षा परिणाम के लिए सरकार की शिक्षा विरोधी नीतियाँ जिम्मेदार: डी.एस.ओ.

गुना : क्रान्तिकारी छात्र संगठन ऑल इण्डिया डी. एस.ओ. ने कक्षा 9वीं के खराब परीक्षा परिणामों के खिलाफ आज स्थानीय सुगन चौराहे पर प्रदर्शन कर विरोध जताया। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष कॉ. सचिन जैन ने कहा कि खराब परीक्षा परिणामों के लिए सरकार की कक्षा 1 से 8 तक पास-फेल प्रणाली खत्म करने व 5वीं-8वीं कक्षा के बोर्ड को खत्म करने जैसी छात्र-विरोधी नीतियाँ ही जिम्मेदार हैं। पूरे प्रदेश का 9वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम 20 फीसदी से भी कम रहा है। यह बेहद शर्मनाक बात है। सरकारी स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। शिक्षकों की ड्यूटी खाना खिलाने, पशु गणना, जनगणना करने आदि में लगा दी जाती है जिससे स्कूलों में पठन-पाठन का माहौल नहीं बन पाता है। सरकार द्वारा लाया गया शिक्षा का अधिकार अधिनियम वास्तव में छात्रों से शिक्षा के अधिकार को छीन रहा है। छात्रों की ड्रॉप आऊट संख्या को कम करने के लिए यह नियम लाया गया था लेकिन इससे ड्रॉप आऊट छात्रों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। साथ ही छात्रों की तर्क-वितर्क करने की क्षमता खत्म कर उन्हें मानसिक रूप से पंगु बनाया जा रहा है। प्रदर्शन को डीएसओ के जिला कार्यकारिणी सदस्य कॉ. विनोद सेन ने भी सम्बोधित किया व संचालन कॉ. मनोज रजाक ने किया।

छात्र आंदोलन की जीत

गुना : म.प्र. सरकार द्वारा सेमेस्टर प्रणाली के लागू होने के 6 वर्ष होने के बावजूद लगातार अनियमितताएँ व अनिश्चितताएँ सामने आ रही हैं। सेमेस्टर प्रणाली में लगातार रिजल्ट में गड़बड़ी, CCE के नम्बर न आना, सेमेस्टर सत्र का सही समय पर न होना, लगातार फीस वृद्धि की समस्याएँ आ रही हैं। इसके खिलाफ में छात्र संगठन एआईडीएसओ लगातार आंदोलनरत है। अभी हाल ही में जीवाजी यूनिवर्सिटी के द्वारा आनन-फानन में जो परीक्षा परिणाम घोषित किये गये वे बेहद खराब रहे। इनमें बी.एस.सी. तृतीय व पंचम सेमेस्टर में 7 हजार से ज्यादा छात्रों को और बी. कॉम तृतीय व पंचम सेमेस्टर में 5 हजार से ज्यादा छात्रों को अनुत्तीर्ण कर दिया गया। खराब परीक्षा परिणाम व सेमेस्टर प्रणाली के खिलाफ यूनिवर्सिटी से संबद्ध कई कॉलेजों के छात्रों ने स्वत:स्फूर्त ढंग से यूनिवर्सिटी का मार्च के महीने में लगातार घेराव किया। एआईडीएसओ की गुना, अशोकनगर , शिवपुरी व ग्वालियर ईकाई द्वारा भी आंदोलन का समर्थन करते हुए उत्तर पुस्तिकाओं का बगैर फीस के पुन: मूल्यांकन करवाने व रिजल्ट की गड़बडियां रोकने की मांग को लेकर यूनिवर्सिटी पर दो बार प्रदर्शन व घेराव किया गया। आंदोलन के दबाव में यूनिवर्सिटी ने पुन: मूल्यांकन करवाया जिसमें कई छात्रों के रिजल्ट में सुधार हुआ और सभी कॉलेजों के नाम इस आशय का एक पत्र जारी किया। लेकिन गुना पी.जी. कॉलेज प्रशासन ने संवेदनहीनता दर्शाते हुए शिक्षकों को यूनिवर्सिटी नहीं भेजा। इसके खिलाफ एआईडीएसओ द्वारा रोष प्रदर्शन किया गया। इसमें सैकडों छात्र शामिल हुए। आन्दोलन के दबाव में कॉलेज प्रशासन शिक्षकों को यूनिवर्सिटी भेजने को राजी हुआ। ऑल इण्डिया डीएसओ के अखिल भारतीय सचिव मंडल सदस्य व जिला अध्यक्ष सचिव जैन ने आंदोलन की जीत पर सभी छात्रों को बधाई दी व सभी छात्रों से लगातार शिक्षा-विरोधी नीतियों व सेमेस्टर प्रणाली के खिलाफ आंदोलन छेड़ने की अपील की।

एआईडीवाईओ का दूसरा जिला सम्मेलन सम्पन्न

मुरादाबाद (उ.प्र.): 25 मई को एआईडीवाईओ जिला मुरादाबाद का दूसरा जिला सम्मेलन स्थानीय गुलजारी मल धर्मशाला में शानदार ढंग से सम्पन्न हुआ। सम्मेलन की अध्यक्षता विनोद विग ने की तथा संचालन मौ. गौरी ने किया। सम्मेलन के मुख्य वक्ता एआईडीवाईओ के प्रदेश अध्यक्ष कॉ. हरकिशोर सिंह थे और मुख्य अतिथि के.जी.के. डिग्री कालेज के प्रो. डॉ. चन्द्रभान यादव थे। सम्मेलन में 100 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कॉ. हरकिशोर सिंह ने कहा कि हाल ही में सम्पन्न 16वीं लोकसभा चुनाव में बुर्जुआ पार्टियों ने युवाओं की असली समस्या बेरोजगारी, जिससे करोड़ों-करोड़ युवा त्रस्त हैं, को नकली मुद्दों में दबा दिया और जातिवाद, साम्प्रदायिकता व क्षेत्रवाद को हवा दी। उन्होंने कहा कि यदि देश में युवा-विरोधी नीतियाँ लागू होंगी तो युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा। सरकार को जनहित की नीतियाँ बनाने के लिए बाध्य करने के लिए युवाओं को जोरदार आन्दोलन चलाकर सरकार पर दबाव बनाना होगा।

मुख्य अतिथि डॉ. चन्द्र भान यादव ने कहा कि आज युवाओं पर हर युग से अधिक बेरोजगारी का दबाव है। मीडिया द्वारा उनके सामने विवेकानन्द और सुभाषचन्द्र बोस जैसे मार्गदर्शकों की बजाय अश्लीलता परोसकर उन्हें राह से भटकाया जा रहा है। गलत शिक्षा नीतियों के कारण युवा शिक्षा से वंचित हो रहा है। सरकारी नौकरियों में नई भर्ती पर पाबंदी है। उन्होंने आगे कहा कि युवाओं के हितों की नीतियाँ बनानी चाहिएं। इसके लिए युवाओं को संघर्ष करना होगा। उन्होंने संगठन के द्वारा संचालित संघर्ष की सराहना की।

सम्मेलन में सर्वसम्मति से 17 सदस्यीय नई जिला कमेटी चुनी गई। जिसमें कॉ. विनोद विग को अध्यक्ष तथा कॉ. मौ. गौरी को सचिव चुना गया। सम्मेलन में दो प्रस्ताव पारित हुए जिनमें एक प्रस्ताव टीएमयू की एमबीबीएस छात्र नीरज भड़ाना की हत्या को 6 जुलाई को एक साल पूरा बीत जाने पर भी हत्यारों की गिरफ्तारी न होने के विरोध में 6 जुलाई को शहर में जुलूस सभा करने से सम्बन्धित था। दूसरा प्रस्ताव शहर में हुए डॉ. शैली मेंहरोदा सहित चार लोगों की हत्या के विरोध से सम्बन्धित था। सम्मेलन को कुलवन्त सिंह, कमलेश चाहल, यशवीर सिंह, नेता सिंह भारती, ऋतु चौधरी, रूबी खान, संध्या त्यागी, मुनीश त्यागी, अमन, शाहआलम, गम्भीर सिंह, राजेन्द्र सिंह, एसयूसीआई(सी) जिला कमेटी इंचार्ज राजपूत ने सम्बोधित किया। सोमवती, लिपि सिंह, रीना रानी, स्वीटी सक्सैना ने क्रान्तिकारी गीत प्रस्तुत किए।

जन समस्याओं पर एसयूसीआई(सी) ने किया प्रदर्शन

दुर्ग (छ.गढ़): 20 मई को एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) पार्टी के कॉ. विश्वजीत हारोडे के नेतृत्व में रामनगर, उरला, शिवपारा, मरारपारा, कातुलबोड़, रायपुर नाका, उड़िया बस्ती, गंजपारा, तितुरडीह, गिरधारी नगर, शीतलानगर, गंजपारा दुर्ग के मौहल्लावासियों ने निगम कार्यालय आकर बताया कि उक्त क्षेत्रों में पेयजल की किल्लत आम है। इसके बावजूद निगम प्रशासन के अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। वर्षों से मांग के बाद भी उक्त क्षेत्र में पाइप लाइन नहीं बिछाई जा रही है। शहर के कई वार्डों में बहुत कम जलापूर्ति की जा रही है। सफाई और गंदे पानी की निकासी की भी समुचित व्यवस्था नहीं है। दूषित पानी पीने के कारण लोग पीलिया के रोग से संक्रमित हैं। पहले भी कई बार प्रदर्शन करके लोग अपना रोष व्यक्त कर चुके हैं। प्रदर्शन के बाद कुछ मौहल्लों में पानी की समस्या का निदान और नालियों की सफाई की कुछ व्यवस्था हुई थी जो अपर्याप्त है। पीने लायक स्वच्छ पानी पर्याप्त मात्रा में सप्लाई करने व सफाई की व्यवस्था करने की मांग को लेकर निगम कार्यालय सचिव को ज्ञापन सौंपा गया। पूर्व सूचना होते हुए भी निगम आयुक्त उठ कर चले गये थे। कलेक्टर को भी मांगों का एक ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने लोगों को उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

पोर्नोग्राफिक वेबसाइट बंद करने की मांग

पोर्नोग्राफिक वेबसाइट पर पाबंदी लगाना सम्भव नहीं –केन्द्र सरकार के अतिरिक्त सोलिस्टर जनरल के इस बयान का ऑल इण्डिया महिला सांस्कृतिक संगठन (एआईएमएसएस) की महासचिव डा. एच जी जयालक्ष्मी ने तीव्र प्रतिवाद किया है। क्योंकि विकृत यौन उत्तेजक हजारों सहजसुलभ वेबसाइटों के प्रभाव के कारण ही समाज में महिलाओं से बलात्कार और अन्य अपराध बढ़ रहे हैं। सूचना तकनीक जगत के विशेज्ञ जब कह रहे हैं कि इस तरह की वेबसाइटें बंद करना सम्भव है और काफी कुछ देशों ने ये बंद कर दी हैं, तब भारत सरकार ऐसा क्यों नहीं कर पा रही है? डा. जयालक्ष्मी ने कहा कि लाखों लाख युवक-युवतियों को इनके नुकसानदेह असर से बचाने की पहलकदमी करने की बजाय इस तरह के फालतू के बहाने बनाने के सरकार के रवैये का पुरजोर प्रतिवाद होना चाहिए।

दिल्ली में मनायी गयी राजा राममोहन राय जयंती

दिल्ली में सभा को सम्बोधित करते हुए प्रो. नरेन्द्र शर्मा

दिल्ली : महान समाज सुधारक राजा राममोहन राय की 242वीं जयंती के अवसर पर शहीद व मनीषी यादगार कमेटी की शालीमार बाग इकाई की ओर से 22 मई को यहां एक सभा का आयोजन किया गया। सभा में शालीमार बाग के कई ब्लाकों से आई महिलाओं ने भारी संख्या में भाग लिया।

सभा की शुरूआत क्रांतिकारी गीतों से हुई। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का संचालन श्रीमती सुमन चौहान ने किया। सभा को शहीद व मनीषी यादगार कमेटी, शालीमार बाग इकाई की संयोजिका श्रीमती नीतू खन्ना, एसयूसीआई(सी) की लोकल कमेटी इंचार्ज प्रकाश देवी, तथा सभा को मुख्य वक्ता के तौर पर शहीद व मनीषी यादगार कमेटी के दिल्ली अध्यक्ष प्रो. नरेन्द्र शर्मा ने सम्बोधित किया।

वक्ताओं ने कहा कि महिलाओं की दयनीय स्थिति, बाल विवाह तथा सती प्रथा के खिलाफ उस समय राजा राममोहन राय द्वारा किया गया संघर्ष बहुत ही प्रेरणादायक है। उस समय में जब महिलाओं को इन्सान का दर्जा तक प्राप्त नहीं था। गोद की मासूम बच्चियों को विवाह के बंधन में बांध दिया जाता था और विधवा होने पर पति के साथ सती कर दिया जाता था। ये सब वीभत्स रस्मो-रिवाज उस समाज की मान्यताओं में शामिल थे। इन बेहद प्रतिकूल परिस्थितियों में राजा राममोहन राय ने समाज में प्रचलित इन कुरीतियों व गलत मान्यताओं के खिलाफ जाकर महिलाओं के इन्सान की तरह जीवन जीने के लिए संघर्ष किया और समाज को नई दिशा दी। आज भी समाज में महिलाओं की स्थिति बहुत खराब है। आज छोटी मासूम बच्चियों से लेकर बूढ़ी मां तक की इज्जत-आबरू और जान सुरक्षित नहीं है। नशाखोरी व अश्लीलता का सीधा असर समाज के नौजवानों और महिलाओं पर गहराई से पड़ रहा है। आज भी एक लड़ाई की ज़रूरत है क्योंकि महिलाओं पर अपराध पुरुषवादी विकृत मानसिकता की पहचान है। इसलिए आज महिलाओं के आन्दोलन को इस पितृसत्तात्मक पूंजीवादी व्यवस्था-विरोधी दिशा देनी होगी और इस संघर्ष को करने लायक बनने के लिए क्रांतिकारी उच्च नीति-नैतिकता को बढ़ावा देने वाला सांस्कृतिक माहौल बनाना जरूरी है। सभा का संचालन श्रीमती शशि वधवा ने किया।

सभा के दूसरे सत्र में डॉ. सुरेखा जैन ने महिलाओं में होने वाले ब्रेस्ट कैंसर और गर्भाशय कैंसर पर व्याख्यान रखा जिसमें महिलाओं ने जिज्ञासा से बहुत से सवाल कर इससे बचाव व इलाज से सम्बंधित सवाल किए। इस सत्र का संचालन श्रीमती मीनू तलवार ने किया।

भवन निर्माण श्रमिकों ने सौंपा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन

रोहतक (हरियाणा) : हरियाणा में भवन निर्माण कार्यों में लगे मजदूर-मिस्त्री नाना समस्याओं से रूबरू हैं। कानून होते हुए भी मजदूर-मिस्त्रियों का पंजीकरण करने में बहुत सारी जटिलताओं का सामना करना पड़ता है। झज्जर, महेन्द्रगढ़ सहित कई जगह पर कोई दफ्तर ही नहीं है जहां पंजीकरण हो सके। पंजीकरण के लिए उन्हें कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। जहां दफ्तर है वहां भी पर्याप्त संख्या में कर्मचारी नहीं हैं। किसी तरह पंजीकरण हो भी जाए तो प्रमाणपत्र के तौर पर उसकी कापियां मिलने में काफी समय लग जाता है। पंजीकृत श्रमिकों को कन्या के विवाह आदि पर मिलने वाली सहायता राशि का लाभ पाने के लिए भी अनेक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बार-बार मांग उठ रही है और सरकार की ओर से कई बार आश्वासन दिये गये हैं लेकिन फिर भी मजदूरों के लिए रैन बसैरों और लेबर चौकों पर शेड-शैल्टरों की व्यवस्था नहीं की गई है। इसके फलस्वरूप राज्य के निर्माणकर्मियों को तो दिक्कत है ही , खास कर दूसरे राज्यों से आये मजदूरों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

इन मांगों को लेकर लम्बे अर्से से आन्दोलनरत है श्रमिक संगठन ऑल इण्डिया यूटीयूसी की हरियाणा शाखा। गत 23 मई को ऑल इण्डिया यूटीयूसी से सम्बन्धित भवन निर्माण कारीगर मजदूर यूनियन ने मांगों के जोरदार नारे लगाते हुए यहां छोटूराम पार्क से लघु सचिवालय तक जुलूस निकाला। जुलूस में महिलाओं समेत भारी संख्या में मजदूर-मिस्त्री शामिल थे। यूनियन के राज्य सचिव कॉ. बलराम यादव, जिला प्रधान सुन्दर, सचिव जगदीश चन्द्र, उपप्रधान सूर्यप्रकाश, सुभाष, सुरेन्द्र, आजाद, शमशेर, जयकिशन आदि श्रमिक नेताओं ने जुलूस की अगुआई की। लघु सचिवालय पहुंच कर उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम अपनी मांगों का ज्ञापन उपायुक्त रोहतक को सौंपा।

ज्ञापन में मांग की गई कि पंजीकरण हेतु जन्म तिथि या उम्र के ऐसे दस्तावेज मान्य किये जायें जो आसानी से उपलब्ध हैं; नियोक्ता मालिक/ठेकेदार के हस्ताक्षर करवाने का प्रावधान आवेदन फार्म से हटाया जाए या इसे अनिवार्य न रखा जाये। पासपोर्ट की तरह पंजीकरण की मान्य अवधि 10 साल हो; नवीनीकरण शुल्क 5 रु. वार्षिक हो; जिला मुख्यालय झज्जर में पंजीकरण कार्यालय व श्रम कार्यालय खोला जाये; अनुसूचित जाति के लाभार्थियों की तरह कन्यादान की राशि विवाह से 15 दिन पहले देने का नियम बनाया जाये। यह राशि 51000 रु. की जाये; विवाह पंजीकरण की शर्त हटाई जाये; विद्यार्थियों के लिए शिक्षा भत्ता पहली कक्षा से लागू हो। दूरस्थ प्रणाली के परीक्षार्थियों को भी इसका लाभ दिया जाये; मकान बनाने के लिए 1. 5 लाख रु. की अग्रिम रकम पंजीकरण के 3 माह से लागू हो और 55 वर्ष की उमर तक मान्य हो; महिला मजदूरों को प्रसूति के समय 6 माह की दिहाड़ी के समान आर्थिक सहायता दी जाये; पैन्शन की रकम बुढ़ापा पैन्शन से दूगुनी 2000 रु. मासिक हो तथा ईएसआई लागू की जाये जिसका मासिक शुल्क 1रु. हो; साईकिल व औजारों के लिए मंजूर रकम जल्द दी जाये; गांवों में 100 गज व शहर में 60 गज के रिहायशी प्लॉट दिये जायें; सैनिकों/वकीलों की तरह हुड्डा द्वारा प्लॉट व मकान अलॉट किये जायें। कार्य स्थल पर सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था हो; मौत होने पर 10 लाख रुपये, चोट लगने पर व अपंग होने पर मुफ्त ईलाज व पर्याप्त मुआवजा दिया जाये; मनरेगा में मजदूरों की दैनिक दिहाड़ी 350 रुपये की जाये; सभी मजदूर-मिस्त्रियों का बीमा हो। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के स्मार्ट कार्ड तुरन्त बनाये जायें और हर तरह की लाभराशि आवेदन के 45 दिन के भीतर-भीतर उपलब्ध करवाई जाये।

रोहतक में अपनी मांगों के लिए सड़कों पर उतरे भवन निर्माण कारीगर-मजदूर

दुनिया और भारत के सबसे अमीर

एक रिपोर्ट कहती है कि दुनिया के सबसे अमीर 85 व्यक्तियों के एक छोटे से कुलीन तबके के पास दुनिया की आबादी के निचले आधे हिस्से के स्वामित्व में जितनी धन-दौलत है उसके बराबर है। कुछ व्यक्तियों के लिए कार्य शीर्षक से यह रिपोर्ट विश्वव्यापी विकास संगठन ऑक्सफेम ने विश्व आर्थिक मंच की दावोस शिखर वार्ता से पहले प्रकाशित की, जिसने इस प्रभाव का विवरण पेश किया कि विकसित और विकासशील देशों में गैर बराबरी की खाई चौड़ी होती जा रही है।

ऑक्सफेम का दावा है कि सबसे अमीरों के इस कुलीन तबके ने लोकतंत्र को खोखला करते हुए और एक ऐसी दुनिया बनाते हुए जिसमें 85 सबसे अमीर दुनिया की आधी आबादी की धन-दौलत के बराबर की धन-दौलत के मालिक हैं, आर्थिक खेल के नियमों में धांधली करने के लिए राजनैतिक शक्ति को सहयोजित किया। इसने यह भी कहा कि 1970 के दशक के आखिरी दौर से 30 में से 29 देशों में जिनके आंकड़े उपलब्ध हैं, इन धनकुबेरों के लिए टैक्स की दरें गिरी हैं, इसका मतलब है कि कई जगहों पर अमीरों को न केवल ज्यादा धन मिल रहा है बल्कि इस पर टैक्स भी कम देना पड़ रहा है।

रिपोर्ट के मुताबिक, गत 25 वर्षों में चन्द हाथों में धन-दौलत और भी ज्यादा संकेन्द्रित हो गई है, इतनी ज्यादा कि दुनिया के 1% परिवार दुनिया की कुल धन-दौलत के लगभग आधे (46%) के मालिक हैं। आक्सफेम चाहता है कि सरकार इस रुझान को उल्टे। विश्व आर्थिक मंच में जो लोग शिरकत करने जा रहे हैं उनसे इस समस्या से निपटने के लिए 6 सूत्री व्यक्तिगत शपथ लेने को यह कह रहा है। यह चौंका देने वाली बात है कि 21वीं सदी में, आधी आबादी के पास एक छोटे से कुलीन तबके के पास जितना धन है उससे ज्यादा नहीं है, जिनकी तादाद इतनी है कि वे सब ट्रेन की एक बोगी में आराम से बैठ सकते हैं, यह बात आक्सफेम के कार्यकारी निदेशक विन्नी बायनयिमा ने कही।

संक्षेप में यह है दुनिया का हाल। अब भारत में तस्वीर क्या है।

भारत में अति उच्च निवल मूल्य व्यक्तियों (अल्ट्रा-हाई नेट वर्थ इण्डिज्युअल्स) यानी धनकुबेरों की संख्या अगले 10 वर्षों में दुगुनी हो जाने का अनुमान है, मुम्बई में 126% और दिल्ली में 118% बढ़ने जा रही है। 60 अरबपतियों के साथ भारत 2013 में अरबपतियों के लिए टॉप 10 देशों में से छठे स्थान पर है। गुरुवार को जारी की गई वैश्विक कंसल्टेन्सी फर्म नाइट फ्रैंक वैल्थ रिपोर्ट के 8वें संस्करण के मुताबिक, 2023 तक इनकी संख्या बढ़ कर 119 हो जाने का अनुमान है। मुम्बई भी लग्जरी घर क्षेत्र में 16वें सबसे महंगे शहर के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखे हुए है। यह सर्वे विश्व स्तर पर निजी बैंकरों और धन सलाहकारों से लिये गये 600 साक्षात्कारों पर आधारित था जो हरेक अपनी खुद की औसतन 68,000,000 डॉलर और 1.5 ट्रिलियन डॉलर से अधिक संयुक्त धन-सम्पदा रखने वाले 23,000 धानकुबेरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रमुख अर्थशास्त्री और नाइट फ्रैंक इण्डिया के डायरेक्टर रिसर्च सामनतक दास ने कहा, ''2013 तक, दुनिया में केवल 3 देशों, अमेरिका, चीन और रूस में भारत से अधिक अरबपति होंगे।'' नाइट फ्रैंक इण्डिया के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक शिशिर बैजल ने कहा, ''अगले दशक में धनकुबेरों (यूएचएनडब्ल्यूआई) की संख्या बढ़कर दुगुनी हो जाने के पूर्वानुमान के साथ भारत में धन-सृजन तेजी से बढ़ जाने का अनुमान है।

दुनिया भर में लगातार जारी आर्थिक अशान्ति के बावजूद अति-धनाढ्य व्यक्तियों की संख्या में पिछले वर्ष 3% बढ़ोतरी हुई। यह कहा कि ''2023 में 30 करोड़ या इससे ज्यादा शुद्ध सम्पत्ति के मालिक इन धनकुबेरों की संख्या अगले दशक में लगभग 30% से ज्यादा बढ़ जाने वाली है।''

न्यूयार्क 2024 तक अति-धनाढ्य व्यक्तियों के लिये सबसे महत्वपूर्ण शहर के रूप में लन्दन से आगे निकल जायेगा। उस वर्ष तक शीर्ष 5 महत्वपूर्ण शहरों में से 3 एशिया में होंगे : हांग कांग, सिंगापुर और संघाई। 2024 में धनकुबेरों (यूएचएनडब्ल्यूआई) के लिए शीर्ष 5 महत्वपूर्ण वैश्विक स्थान क्रमशः लन्दन, न्यूयार्क, सिंगापुर, हांग कांग और जेनेवा हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में सैकड़ा-करोड़पति (जिनके पास 100 करोड़ डॉलर विक्रय योग्य सम्पत्ति है) वे भी पिछले साल के 383 से 99% बढ़ कर 2023 में 761 हो जाने का अनुमान है। एशिया में अरबपतियों की संख्या भी अगले दशक में यूरोप की संख्या को पार कर जाने का पूर्वानुमान है। एशिया के शहर भी अगले दशक में अति अमीरों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी देखने की उम्मीद कर रहे हैं। इस वैल्थ रिपोर्ट के प्राइम अन्तराष्ट्रीय आवासीय सूचकांक से प्राप्त नवीनतम परिणम दिखाते हैं कि जकार्ता के नेतृत्व में एशियाई बाजारों ने 2013 में सबसे बड़ी मूल्य वृद्धि महसूस की, उसके बाद ऑकलैण्ड, बाली, क्राइस्टचर्च और डब्लिन ने। जकार्ता में औसत मूल्य परिवर्तन (2012-2013 में) 37.7% था।

(सूत्र : टाइम्स ऑफ इण्डिया)

छात्रों की ज्वलंत समस्याओं के खिलाफ छात्र प्रदर्शन

भुवनेश्वर : ऑल इण्डिया डेमोक्रेटिक स्टूडेन्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के नेतृत्व में छात्रों और अभिभावकों ने 3 जून को भुवनेश्वर में काउन्सिल ऑफ हायर एज्यूकेशन (सीएचएसई), ओडिशा के सामने प्रदर्शन किया। वे मांग कर रहे थे कि सभी पेपरों का पुनःमूल्यांकन किया जाये और रिएडमिशन फीस व छात्रों से उत्तर पुस्तिकाओं की फोटोकापी का शुल्क माफ किया जाए। एआईडीएसओ ने उत्तर पुस्तिकाओं का गलत मूल्यांकन करने वालों को सख्त सजा देने की भी मांग की। सीएचएसई अधिकारियों ने उत्तर पुस्तिकाओं की फोटोकापी की बढ़ी हुई फीस 600 रुपये से घटा कर 200 रुपये और रिएडमिशन फीस भी 300 रुपये से घटा कर 100 रुपये कर दी।

कॉमरेड रामजोर मौर्य का निधन

एसयूसीआई (कम्युनिस्ट), मुम्बई के कॉमरेड रामजोर मौर्य नहीं रहे। ब्रेन हैम्रेज की वजह से 12 मई को उनका निधन हो गया। हालांकि वे यू.पी. के जौनपुर जिले की बदलापुर तहसील के साथ ढीले ढाले ढंग से जुड़े थे लेकिन आगरा से कृषि में एमएससी की अपनी शिक्षा के बाद वे मुम्बई के पास भिवण्डी में आकर बस गये थे जो भारत में पावरलूम के सबसे बड़े केन्द्र के रूप में विख्यात है। भिवण्डी में उन्होंने अपने परिवार के आग्रह पर अपने संयुक्त परिवार के मालिकाने में पावरलूम का प्रबंध किया और सैकेण्ड क्लास अफसर की सरकारी नौकरी की पेशकश ठुकरा दी थी। यह टैक्सटाइल उद्योग में गहन संकट का जमाना था और एक ट्रेड यूनियन नेता दत्ता सामन्त के आह्वान पर मुम्बई में हुई हड़ताल का दौर था। यहां वे मुम्बई और पुना में पार्टी निर्माण के काम में जुटे कॉमरेड द्वारकानाथ रथ के सम्पर्क में आये और कॉमरेड शिवदास घोष के चिन्तन से गहरे प्रभावित हुए। उस आर्थिक संकट में वे अपनी पावरलूम फैक्टरी गवां बैठे लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाने के बावजूद मरते दम तक कॉमरेडों से अपना रिश्ता और कॉमरेडशिप कभी नहीं गवांयी। अपने जीवन के अन्तिम वर्षों में अपनी खराब सेहत के बावजूद उन्होंने मुम्बई में पार्टी के हर किसी कार्यक्रम में शिरकत करना नहीं छोड़ा। पार्टी की मुम्बई इकाई की ओर से 18 मई को भिवण्डी में उनकी स्मृति सभा आयोजित की गई जिसकी अध्यक्षता कॉमरेड कुमार कुलश्रेष्ठ ने की।

परिचर्चा का आयोजन

दिल्ली : ऑल इण्डिया सेव एजूकेशन कमेटी की करोल बाग ईकाई द्वारा 1 जून को स्थानीय पार्क में एक परिचर्चा आयोजित की गई जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। परिचर्चा का विषय था 'शिक्षा व संस्कृति'। लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे हमले और सांस्कृतिक पतन पर गहरी चिन्ता जतायी। शिक्षा का महत्व समझाते हुए उपस्थित जनसमूह को सम्बोधित करते हुए मुख्य वक्ता कॉ. गिरवर सिंह ने बताया कि शिक्षा कैसे नये समाज के निर्माण में अहम भूमिका निभाती है। जबकि आज मुनाफा कमाने के लिए शासक पूंजीपति वर्ग शिक्षा के स्वरूप को ही बदल देना चाहता है और शिक्षा के क्षेत्र को व्यापार करने के बिकाऊ माल में तब्दील करता जा रहा है। शिक्षा के गिरते स्तर के कारण इन्सान बनाने वाली और चरित्र निर्माण करने वाली शिक्षा नहीं दी जा रही है। नतीजतन बड़ी तेजी से सांस्कृतिक पतन हो रहा है। उन्होंने शिक्षा-संस्कृति को बचाने के लिए आन्दोलन तेज करने की अपील की।

सभा का संचालन कॉ. राहुल सरकार ने किया।

R.N.I. No.- 43022/85
P.R.No.-DL(C)-01/1123/2012-2014
Posting at IPMBC on 7–8 and 22–23 Fortnightly, Date of Printing : 5June, 2014

विश्व कप की चकाचौंध में बहलायी नहीं जा सकती ब्राजील की जनता

आगामी 12 जून को शुरू हो रहा है विश्व कप फुटबाल। कई महीनों से मीडिया में चल रहा है उसका धुंआधार प्रचार–रंग–बिरंगे विज्ञापन, रोशनी की झिलमिल सजावट, करोड़ों करोड़ रुपये का कारोबार। जिस देश में उड़ाये जा रहे हैं विश्व कप फुटबाल के ये रंगीन गुब्बारे–कैसे हैं उस ब्राजील के आम आदमी।

16 मई को ब्राजील के सबसे बड़े शहर साओ पावलो, जिस शहर में 13 जुलाई को विश्व कप का फाइनल मैच होगा उस रिओ–डी–जेनेरो शहर से लेकर और भी कई शहरों में इस खर्चीले विश्व कप के खिलाफ हजारों हजार लोगों का रोष फूट पड़ा। शिक्षक, सरकारी नौकरीपेशा लोग भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गये हैं। कई जगह पर रास्ता रोको, हड़तालें हो रही हैं। देश के लोग जब सिर पर छत नहीं, जब काफी संख्या में आम आदमी के जीवन में गरीबी, अनिश्चितता लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसे में इस फुटबाल टुर्नामेंट के पीछे देश की सरकार करोड़ों डॉलर खर्च करने जा रही है। बेघर लोगों के लिए मकान तैयार करने में पैसा खर्च करने की बजाय वह बड़े–बड़े स्टेडियम बनवा रही है, जहां विश्व कप के उन्माद में और आमोद–प्रमोद में दर्शक झूमेंगे। इसलिए जो खेल ब्राजील के लोगों से ओतप्रोत रूप से जुड़ा हुआ है, वह आज उनकी नजरों में 'वीभत्स मजा' है। इसी के खिलाफ पुलिस की आँसू गैस के सामने ब्राजील का आम आदमी अपने रोष का इजहार कर रहा है। बहुत दिनों से जमा इस विक्षोभ के वाष्प साओ पावलो से लेकर विस्फोट सा हो कर इटाकुयेराओ जिले में फैलते जा रहे हैं। इस जिले के एक स्टेडियम में ही विश्व कप का उद्घाटन मैच होने की बात है। 'होमलैस वर्कर्स मूवमेन्ट' के एक नेता ने बताया कि स्टेडियम को तोड़ना उनका मकसद नहीं है। वे चाहते हैं मेहनतकश लोगों के अधिकार, चाहते हैं सिर छुपाने के

लिए आश्रय। विश्व कप के इस निर्लज्ज आडम्बर ने इस देश के गरीब लोगों को क्या दिया है या क्या देना है–वही जानना चाहते हैं वे लोग।

स्वाभाविक है कि ब्राजील सरकार अपना चेहरा बचाने के लिए आम आदमी के इस विक्षोभ को महत्वहीन सा दिखाना चाह रही है। खेलमंत्री आल्डो रेबेलो ने कहा है, 'इससे विश्व कप का कोई लेना–देना नहीं है। मजदूरों ने अपनी कुछ माँगें माँगी हैं।' लेकिन सरकार की ओर से असल तस्वीर को छिपाने की चाहे जितनी भी कोशिश क्यों न हो, दिये तले अन्धेरा है यह और भी साफ हो गया है इस दिन हुए रोष प्रदर्शन से। खेल, आनन्द लोंगों के लिए ही होता है। उन लोगों के जीवन को ही विपन्न कर फुटबाल के नाम पर यह करोड़ों करोड़ रुपये का कारोबार लोग हरगिज मंजूर नहीं करेंगे। स्वत:स्फूर्त विक्षोभ दीर्घस्थायी आन्दोलन का रूप लेगा, ऐसा मानना है ब्राजील के शोषित–वंचित लोगों का। (सूत्र : बीबीसी न्यूज –16 मई, 2014)

बच्चों के यौन उत्पीड़न पर एआईएमएसएस ने जतायी गहरी चिन्ता

पुना में, जैसी कि 30 मई को मीडिया में खबर छपी है, चन्द्रपर्व चैरिटेबल ट्रस्ट नामक ''होम'' के बच्चों से यौन उत्पीड़न की घटी गम्भीर घटना पर ऑल इण्डिया महिला सांस्कृतिक संगठन (एआईएमएसएस) की महासचिव डा. एच जी जयालक्ष्मी ने 31 मई को जारी किये गये एक बयान के जरिये अपनी गहरी चिन्ता और व्यथा–वेदना प्रकट की।

उन्होंने इस होम में बच्चों पर किये गये अनैतिक और आपराधिक करतूतों की निन्दा की और महाराष्ट्र सरकार से दुष्कर्मियों को उदाहरणमूलक सजा देने की मांग की। उन्होंने पीड़ित बच्चों के उचित इलाज और पुनर्वास की भी मांग की। अथोरिटी भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावर्ती रोकने के लिए ऐसे होमों की निगरानी को सुनिश्चित करें।

गुजरात में अमूल दूध के दामों और बिजली दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ सूरत चौक पर प्रदर्शन करते हुए एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) पार्टी के कार्यकर्ता

बदायूँ व बरेली जिले में हुए बलात्कार व हत्याकाण्ड के विरोध में प्रदर्शन

नई दिल्ली दिल्ली : ऑल इण्डिया महिला सांस्कृतिक संगठन की दिल्ली राज्य कमेटी द्वारा उत्तर प्रदेश के बदायूँ जिले में दो लड़कियों के साथ हुई बलात्कार और नृशंस हत्याकाण्ड तथा बरेली जिले में एक 22 वर्षीय युवती के साथ हुई सामूहिक बलात्कार और उसे जबरन तेजाब पिलाकर हत्या कर देने की घटना के के खिलाफ 4 जून को 4, सरदार पटेल मार्ग, उत्तर प्रदेश भवन के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया जिसमें दिल्ली के विभिन्न इलाकों से आई महिलाओं ने हिस्सा लिया। विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई सभा को ए.आई.एम.एस.एस. की दिल्ली राज्य कमेटी की उपाध्यक्ष श्रीमती पुष्पा चमोली और दिल्ली राज्य सचिव रितु कौशिक, सचिवमण्डल सदस्य सीता सिंह, आशा रानी, सुमन यादव और कमेटी सदस्य संध्या विश्वकर्मा ने अपनी बात रखी। विरोध सभा को एस.यू.सी.आई.(सी) की दिल्ली राज्य कमेटी के सचिवमण्डल सदस्य कॉमरेड रमेश शर्मा ने भी सम्बोधित किया।

वक्ताओं ने कहा कि देशभर में महिलाओं पर बढ़ते अपराध और इन घटनाओं में प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से पुलिस, प्रशासन तथा राजनैतिक हस्तियों का संलिप्त होना हमारे समाज में व्याप्त पितृसत्तात्मक मानसिकता को दर्शाता है। इसका उदाहरण हम पिछले दिनों समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव की एक टिप्पणी के रूप में देखते हैं। इस प्रकार की घृणित टिप्पणियाँ असामाजिक तत्वों को तथा महिलाओं पर बढ़ते अपराधों को और अधिक बढ़ावा देती हैं। वक्ताओं ने कहा कि समाज के लोकतान्त्रीकरण से ही महिलाओं पर बढ़ती बलात्कार की घटनाओं को रोका जा सकता है। उसके लिए एक व्यापक सामाजिक–सांस्कृतिक आंदोलन की आवश्यकता है ताकि समाज में महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक समझने वाली पितृसत्तात्मक मानसिकता को समाप्त किया जा सके। वक्ताओं ने कहा कि मीडिया द्वारा फैलाई जा रही अश्लीलता और हिंसा तथा शराब के प्रसार के कारण महिलाओं पर बढ़ते अपराधों को लगातार बढ़ावा मिल रहा है। भूमण्डलीकरण, निजीकरण व उदारीकरण की जनविरोधी नीतियों के चलते महिलाओं को उपभोग की वस्तु में रूपांतरित किया जा रहा है। इस रुझान की सबसे भद्दी अभिव्यक्ति तथाकथित सौन्दर्य प्रतियोगिताओं व प्रदर्शनियों के बढ़ते प्रचलन के रूप में हुई है। उपभोक्तावादी संस्कृति को फैलाने के लिए भी नारी को ही निशाना बनाया जा रहा है। बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, यहाँ तक कि बलात्कार के बाद हत्या, यौन उत्पीड़न के अपराधों को नजरअंदाज कर पुलिस–प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही न होने के कारण ऐसी आपराधिक मनोवृत्ति को संरक्षण मिल रहा है जिसके चलते अपराधी सीना तान कर खुलेआम घूमने की छूट पा चुके हैं।

वक्ताओं ने दोषियों को उदाहरणमूलक सजा देने की मांग करते हुए महिलाओं पर बढ़ते अपराधों के खिलाफ देश के तमाम छात्र–नौजवानों, विशेषकर महिलाओं से जोरदार आन्दोलन खड़ा करने की अपील की।

उत्तर प्रदेश भवन के सामने विरोध प्रदर्शन करती हुई महिला सांस्कृतिक संगठन की कार्यकर्ता

सोशलिस्ट यूनिटी सेन्टर ऑफ इण्डिया (कम्युनिस्ट) की ओर से कॉ. सत्यवान द्वारा 3ए/38, डब्ल्यू.ई.ए., करोल बाग. नई दिल्ली-5 से संपादित व प्रकाशित तथा परम्परा प्रिंटिंग प्रेस, बी-70/83, इण्डस्ट्रियल एरिया, लॉरेंस रोड, दिल्ली-35 से मुद्रित, दूरभाष:011-25726631, Email: sarvaharadrishtikon@gmail.com; sarvaharadrishtikon@yahoo.com